

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR**

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK AGARWAL

ON THE 6th OF APRIL, 2022

MISC. CRIMINAL CASE No. 15874 of 2022

Between:-

INDRAJEET PATEL

.....PETITIONER

(BY SHRI UMA SHANKAR JAYASWAL, COUNSEL FOR THE APPLICANT)

AND

**THE STATE OF M.P. THROUGH P.S. MAIHAR DISTRICT SATNA (M.P.) (MADHYA
PRADESH)**

.....RESPONDENTS

(BY SHRI VIVEK LAKHERA, GOVERNMENT ADVOCATE)

This application coming on for admission this day, the court passed the following:

ORDER

This is second bail application filed under Section 439 of the Code of Criminal Procedure 1973.

The first bail application M.Cr.C. No. 10856/2022 was dismissed as withdrawn vide order dated 4/03/2022 but at that time, a charge-sheet was not filed. When charge-sheet is filed, then the applicant has filed this repeat application.

Learned counsel for the applicant submits that the learned court of 1st Additional Sessions Judge, Maihar, District Satna granted bail to main accused Ajay @ Guddu Mishra from whom stolen property was recovered vide order dated 12/02/2022 purely on caste lines whereas bail application of the present applicant was dismissed, though he was made an accused on the basis of memorandum of co-accused Ajay Mishra and no recovery has been made from him.

It is further submitted that there is a criminal history of six cases against co-accused Ajay Mishra whereas criminal history of ten cases against the present applicant and like Ajay Mishra, there is no order of conviction in any of the pending cases against the present applicant as has been mentioned *qua* Ajay Mishra. It is pointed out that learned Additional Sessions Judge has exercised the discretion in an arbitrary and illegal manner.

Before expressing any opinion it will be pendent to quote relevant portion of consideration of bail application made by learned Additional Session Judge in case of Ajay @ Guddu Mishra in bail application No.45/2022 decided on 12.02.2022.

विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा-27 साक्ष्य विधान बनाया गया। आरोपी के कब्जे से चोरीशुदा मोटर सायकल क्रमांक एम पी 19 एम एल/4930 को जप्त किया जाना बताया गया है तथा अन्य कोई जप्ती आदि की

कार्यवाही शेष न होना बताया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान इस बात पर जोर दिया है कि आरोपी का अपराध अधिकतम धारा-401 एवं 414 भा0द0वि0 की परिधि का है, जो सात वर्ष से कम अवधि से दण्डनीय है। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है एवं आपराधिक रिकार्ड के संबंध में आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन द्वारा दी गई आपराधिक सूची के संबंध में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी को अन्य किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक टी0बी0 की बीमारी से भी ग्रसित है जिससे संबंधित दस्तावेज रिमाण्ड पत्रावली में है। आरोपी दिनांक 05/02/2022 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगना संभावित है।

फलतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त अजय उर्फ गुड्डू मिश्रा की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0स0 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर, जिला सतना की संतुष्टि योग्य 25,000/- रूपएं की सक्षम स्थानीय जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे धारा-437(3) द0प्र0स0 में दी गई शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे।

Material on which consideration was bestowed by the concerned Additional Sessions Judge while dismissing the application No.54/2022 vide order dated 21.02.2022.

विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा-27 साक्ष्य विधान बनाया गया। आवेदकगण/आरोपीगण ने अपने

मेमोरेण्डम में मोटरसाईकिल की चोरी किया जाना बताया है। आवेदकगण/आरोपीगण को चोरी की गैंग का सदस्य होना बताया गया है। केस डायरी के साथ आवेदकगण/आरोपीगण का आपराधिक रिकार्ड संलग्न है जिसमें आवेदकगण/आरोपीगण के विरुद्ध सतना एवं रीवा में चोरी से संबंधित अपराध पंजीबद्ध होना दर्शित है जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण/आरोपीगण चोरी के आदतन अपराधी हैं। जहां तक समानता के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है, तो जमानत प्राप्त सहअभियुक्त अजय उर्फ गुड्डू मिश्रा का मामला आवेदकगण/अभियुक्तगण से भिन्न होने के आधार पर आवेदकगण/आरोपीगण को समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। समानता के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्त जिसे जमानत का लाभ दिया गया है, के विरुद्ध केवल यह अभियोग है कि उसके द्वारा चोरीशुदा मोटरसाईकिल को प्राप्त किया गया है, उसका आपराधिक रिकार्ड भी चोरी के संबंध में अत्याधिक नहीं था जबकि उक्त दोनों आरोपीगण के विरुद्ध ताला तोड़कर रात्रि में स्वयं चोरी किये जाने का अभियोग है तथा चोरी के अन्य कई सारे प्रकरण भी उनके विरुद्ध पंजीबद्ध है। वर्तमान समय में मोटरसाईकिलो की चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण/अभियुक्तगण **इन्द्रजीत पटेल एवं राजकुमार उर्फ लल्लू** की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 द0प्र0स0 सद्भावी न होने से **निरस्त** किया जाता है।

Taking into consideration the material reproduced above, it is a fact that the learned 1st Additional Sessions Judge Prashant Shukla had granted bail to the co-accused from whose possession, a stolen property was recovered but denied bail to

the present applicant, *prima facie* substantiates the allegations made by learned counsel for the applicant.

Considering the fact that case of the present applicant is on better footing than Ajay @ Guddu Mishra from whom, a stolen property was recovered, the bail is extended to the present applicant. In view of such facts, the application is **allowed.**

It is directed that applicant be released on bail on his furnishing a personal bond in the sum of **Rs.25,000/- (Rupees Twenty five Thousand Only)** with two solvent sureties in the like amount to the satisfaction of the Trial Court concerned for his appearance before the said Court on all such dates as may be fixed in this regard during pendency of the trial. The applicant shall abide by the conditions as enumerated under Section 437(3) of Cr.P.C.

This order shall be effective till the end of the trial, however, in case of bail jump and breach of any of the pre-condition of bail, it shall become ineffective.

In view of the outbreak of new mutant Omicron of COVID-19, the jail authorities and the State Government are directed to follow the guidelines issued by the Health Ministry in the wake of Novel Corona Virus/Omicron virus before and after releasing the applicant.

Let warning be issued to the concerned Judge Shri Prashant Shukla, First Additional Session Judge, Maihar, District Satna and copy of this order and warning be placed in his service book to be more cautious and judicious in his approach in future so that image of the judiciary can be saved and such allegations of casteism and bias are not allowed to be levied so to tarnish collective image of judiciary.

vy/

(VIVEK AGARWAL)

JUDGE